April 30, 2020

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Department
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai-400 001

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza
5th Floor, Plot no C/1, G Block
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai 400 051.

Subject: Newspaper publication – Board meeting intimation

Dear Sir/Ma'am,

We wish to inform you that pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the "Notice of Board meeting intimation" in the following newspapers:

a) Business Standard (Hindi)
b) Business Standard (English)

Copy of newspaper clippings are attached.

Kindly take this on record and acknowledge receipt.

Thanking you,

Yours truly,

For **NIIT Technologies Limited**

LALIT KUMAR SHARMA
Digitally signed by LALIT KUMAR SHARMA
Date: 2020.04.30 18:06:34 +05'30'

Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel

Encl: as above

खबरों में रहे स्टॉक

ऐक्सिस बैंक

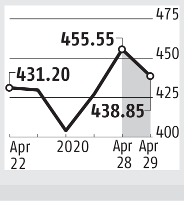

कोविड-19 प्रकोप के कारण इक्विटी पर रिटर्न में सुधार के आसार कम
455.55 पिछला बंद भाव
438.85 आज का बंद भाव
▼ 3.67 %

एचडीएफसी

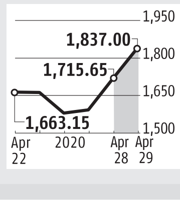

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर
₹ 1,715.65 पिछला बंद भाव
₹ 1,837.00 आज का बंद भाव
▲ 7.07 %

मदरसन सुमी सिस्टम्स

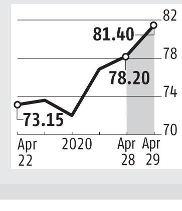

वैश्विक स्तर पर अधिकतर संयंत्रों का परिचालन सुचारु
₹ 78.20 पिछला बंद भाव
₹ 81.40 आज का बंद भाव
▲ 4.09 %

हेक्सावेयर टेक्नोलॉजिज

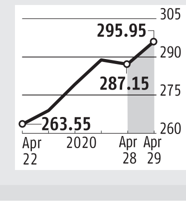

मार्च तिमाही में कर पूर्व लाभ 27 फीसदी बढ़ा
₹ 287.15 पिछला बंद भाव
₹ 295.95 आज का बंद भाव
▲ 3.06 %

सेल

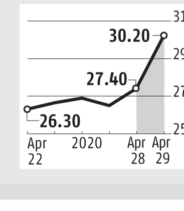

एसऐंडपी बीएसई धातु सूचकांक में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर
₹ 27.40 पिछला बंद भाव
₹ 30.20 आज का बंद भाव
▲ 10.22 %

संक्षेप में

ब्लैकबक ट्रकों के लिए अभी नहीं लेगी कमीशन

ट्रकिंग प्रौद्योगिकी कंपनी ब्लैकबक ने कहा है कि उसने लॉजिस्टिक उद्योग को मौजूदा संकट से उबारने में मदद करने और माल की आवाजाही को रफ्तार देने के लिए कई उपाय किए हैं। कंपनी द्वारा शुरू की गई 'मूव इंडिया' पहल का उद्देश्य ट्रकों के परिचालन को बेहतर करना और देश में आपूर्ति व्यवस्था सुचारु करते हुए आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधाओं को दूर करना है। कंपनी ने कहा है कि विनिर्माता, व्यापारी एवं अन्य कारोबारी यदि अपना उत्पादन शुरू कर चुके हैं अथवा उनके पास स्टॉक तैयार है तो वे ब्लैकबक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए करीब 10 लाख ट्रकों को ऐक्सेस कर सके हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिये देश भर में अपने उत्पादों की आपूर्ति के लिए वे कम कीमत पर तत्काल बुकिंग कर सकते हैं। *बीएस*

फंसी संपत्ति खरीदेगी बजाज हेल्थकेयर

बजाज हेल्थकेयर ने बुधवार को कहा कि वह सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक से 61 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र व गुजरात में स्थित भूखंड व कारखाना समेत कुछ फंसी संपत्तियां खरीदेगी। बजाज हेल्थकेयर ने स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि खरीदी जा रही संपत्तियों की मौजूदा क्षमता प्रति माह 111 टन दवाएं बनाने की है। ये संपत्तियां मेफेनेमिक एसिड, आर्टीमीथर, ल्यूमेफ्रेनरिन, एसीक्लोफीनेक अल्बेंडाजोल और नीमोसुलाइड जैसी दवाएं व सक्रिय औषधि अवयवों का थोक में उत्पादन करने में सक्षम हैं। कंपनी महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड और कारखाने का भवन खरीद रही है। *भाषा*

कोविड-19 की दवा का निर्यात

स्ट्राइड्स फार्मा ने एंटीवायरल बायोसिमिलर दवा तैयार कर शुरू किया निर्यात

समरीन अहमद
बेंगलूरु, 29 अप्रैल

प्रमुख औषधि कंपनी स्ट्राइड्स फार्मा साइंस ने कोवड-19 के उपचार के लिए एक एंटीवायरल बायोसिमिलर दवा विकसित की है। कंपनी अब उसकी बिक्री भी शुरू कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि यह दवा कोविड-19 की अवधि को घटाने और रोगियों के फेफरे की हालत में सुधार लाने में समर्थ है।

फैविपिरैविर दवा एविगन का जेनेरिक संस्करण है जिसे सबसे पहले जापान में इन्फ्लूएंजा के उपचार के लिए विकसित किया गया था। फिलहाल इस दवा का निर्यात खाड़ी देशों को किया जा रहा है। कोविड-19 के उपचार के लिए उनके कार्यक्रम के तहत रोगियों के उपचार के लिए किया जा रहा है। सरकारी कार्यबल द्वारा इस वायरस के खिलाफ जंग में इसे एक प्रमुख दवा माना गया है।

स्ट्राइड्स फार्मा साइंस के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक आर अनंतनारायणन ने कहा, 'हम ऐसी पहली भारतीय कंपनी हैं जिसने वैश्विक बाजारों के लिए फैविपिरैविर टैबलेट का विकास करने के साथ-साथ वाणिज्यिक तौर पर उसे लॉन्च भी किया है। यह दवा दुनिया भर के लाखों लोगों को सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिहाज से अहम भूमिका निभाएगी।' उन्होंने कहा कि यह दवा बाजार में 400 एमजी और 200 एमजी क्षमता के साथ उपलब्ध है।

स्ट्राइड्स भारतीय रोगियों के लिए इस दवा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए और आवश्यक अध्ययन के लिए भारतीय दवा नियामक के पास आवेदन भी करेगी। इस टैबलेट का उत्पादन स्ट्राइड्स के बेंगलूरु संयंत्र में किया जा रहा है। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता सालाना 6 अरब टैबलेट की है।

कंपनी ने फैविपिरैविर एपीआई की आपूर्ति के लिए एक भारतीय एपीआई विनिर्माता के साथ तरजीही व्यवस्था के लिए करार किया है। साझेदार कंपनी स्ट्राइड्स के विनिर्माण संयंत्र से फैविपिरैविर एपीआई की खरीद-बिक्री पहले ही शुरू कर चुकी है।

स्ट्राइड्स मलेरिया, हैपेटाइटिस और अन्य संक्रमण संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए दवाओं की आपूर्ति करती है।

एंटीवायरल दवाओं के वैश्विक बाजार का आकार 2022 तक 62.67 अरब डॉलर के पार पहुंचने की उम्मीद है। भविष्यवाणी की अवधि यानी 2015 से 2022 के बीच यह वृद्धि 6.9 फीसदी सीएजीआर की होगी।

जायडस कैडिला, सिप्ला, ग्लेनमार्क और डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज जैसी प्रमुख भारतीय दवा कंपनियां एंटीवायरल दवाओं के विकास पर काम कर रही हैं।

मुंबई की कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ने फैविपिरैविर की मंजूरी के लिए डीसीजीआई से संपर्क किया है। कंपनी तीसरे चरण के परीक्षण के तहत इसका प्रयोग 100 से 150 रोगियों पर करेगी।

कोरोनावायरस की दवा

- फैविपिरैविर दवा एविगन का जेनेरिक संस्करण है जिसे सबसे पहले जापान में इन्फ्लूएंजा के उपचार के लिए विकसित किया गया था
- फिलहाल इस दवा का निर्यात खाड़ी देशों को किया जा रहा है

टीकों का उत्पादन 2021 के मध्य तक : जीएसके

टीका बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने कहा है कि कोरोनावायरस का टीका विकसित करने में वैश्विक दबाव के बावजूद बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन अगले साल की दूसरी छमाही से पहले नहीं होगा। कंपनी की सीईओ वाम्सले ने पहली तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद संवाददाओं से बातचीत में कहा, 'यदि सब ठीक रहा तो लाखों खुराक का उत्पादन अगले साल दूसरी छमाही तक शुरू हो जाएगा।' उन्होंने कहा कि इसके लिए टीका के विकास में तेजी से वैश्विक प्रयास की जरूरत होगी ताकि यह पता चल सके कि यह टीका सुरक्षित, प्रभावी और असरदार है। *रॉयटर्स*

स्थानीय विनिर्माता बना रहे आरएनए निष्कर्षण किट

सोहिनी दासऔर विनय उमरजी
मुंबई / नई दिल्ली, 29 अप्रैल

भारत में कोविड-19 के परीक्षण के लिए इस्तेमाल की जा रही एंटीबॉडी परीक्षण किट की गुणवत्ता तथा कीमत पर सवाल उठने के बाद आणविक परीक्षण विधि (जिसे आरटी-पीसीआर नाम से भी जाना जाता है) की ओर देखा जा रहा है। इसलिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट निर्माता पूरी क्षमता के साथ किट उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं।

भारत ने प्रतिदिन एक लाख नमूनों का परीक्षण करने की योजना बनाई है और स्थानीय स्तर पर किट निर्माण के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं है।

केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे चीनी कंपनियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली एंटीबॉडी परीक्षण किट का उपयोग करना बंद कर दें। इसके चलते आरटी-पीसीआर परीक्षण किट की मांग में तेजी आई है। साथ ही, किट के आयात में आने वाली परेशानी के बीच मायलैब तथा कोसारा डायग्वनोस्टिक्स जैसी स्वदेशी प्रयोगशालाएं उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही हैं।

रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) टेस्ट आरएनए-निष्कर्षण किट के बिना नहीं किया जा सकता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) में वायरस की आनुवंशिक जानकारी होती है। एक सफल और सटीक पीसीआर परीक्षण (एक आणविक परीक्षण) के लिए पर्याप्त मात्रा में वायरस आरएनए को निकालना आवश्यक है। अगर किट पर्याप्त मात्रा में वायरस का आरएनए नहीं निकाल पाता तो आरटी-पीसीआर किट की कोई अहमियत नहीं रह जाती।

मायलैब के प्रबंध निदेशक हसमुख रावल ने कहा, 'हमें अपने आरएनए निष्कर्षण किट के लिए आईसीएमआर से मंजूरी मिली है। हमने पिछले शनिवार से ही इन किटों का निर्माण शुरू कर दिया है।' उन्होंने कहा, 'हमने कच्चे माल के लिए इन्वेंट्री बिल्डिंग पर काम करना शुरू कर दिया है। अब हम मई के पहले सप्ताह तक प्रति दिन 200,000 आरटी-पीसीआर किट बनाने में सक्षम होंगे।' कंपनी ने अब तक तीन लाख आरटी-पीसीआर किटों की आपूर्ति की है और मई के पहले सप्ताह तक यह चार लाख किटों की आपूर्ति करेगी।

कंपनी ने 28 दिनों के स्टॉक की योजना के साथ आरटी-पीसीआर किट का निर्माण शुरू किया है। रावल ने कहा कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है, और कुछ मामलों में 3.5 से चार गुना तक तेजी आई है। हालांकि कंपनी ने अपने किट के मूल्य (1,200 रुपये प्रति किट) में बदलाव नहीं किया है।

इसी तरह, अहमदाबाद स्थित कोसारा डायग्नोस्टिक लिमिटेड बढ़ती मांग के आधार पर अपनी 20000 किट प्रति दिन की क्षमता को दोगुना करने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एएसई के प्रबंध निदेशक मोहल साराभाई ने कहा कि कंपनी अपने वडोदरा संयंत्र में विनिर्माण क्षमता का विस्तार कर रही है। भारतीय के संदर्भ यह अधिक महत्त्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि देश में फिलहाल तीन लाख आरएनए निष्कर्षण किट हैं। और अधिक किट मंगवाई गई हैं लेकिन उन्हें आने में समय लगेगा। स्वदेशी किट होने से परीक्षण में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

सूत्रों का कहना है कि भारत में लगभग तीन लाख आरएनए निष्कर्षण किट हैं और परीक्षण की वर्तमान दर (लगभग 38,000 परीक्षण प्रति दिन) के हिसाब से ये किट केवल एक सप्ताह तक चलेंगी। मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही संकेत दिया है कि आरएनए निष्कर्षण किट की संख्या तेजी से कम हो रही है।

यूको बैंक UCO BANK
Honours Your Trust
(A Govt. of India Undertaking)
Risk Management Department
Head Office, 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
NOTICE
Request for Proposal (RFP) for Engagement of a Credit Rating Agency for **Recalibration / Design / Vetting of the Internal Credit Rating Models and hoisting** on Bank's portal. Please visit Bank's website **https://www.ucobank.com** for details.

यूको बैंक UCO BANK
सम्मान आपके विश्वास का
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्रधान कार्यालय - II, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3 और 4, डी डी ब्लॉक, सेक्टर -I, साल्ट लेक, कोलकाता - 700064
निविदा की सूचना
यूको बैंक निम्नलिखित मदों के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर.एफ.पी) आमंत्रित करता हैं:-
1. एसएमएस एग्रीगेटर के रुप में सेवा प्रदाता के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी)।
2. आई.टी. कंसलटेंट (रीटेनेर बेसिस) के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी)।
3. फासटेग जारी करने हेतु जारीकर्ता (ओपेक्स मॉडल) तथा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एन.ई.टी.सी)के कार्यान्वयन के लिए विक्रेता के चयन हेतु प्रस्ताव के लिए अनुरोध(आर.एफ.पी)।
किसी भी विवरण के लिए कृपया **https://www.ucobank.com** वेबसाइट पर देखें।
दिनांक :30.04.2020 उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बीपीआर एवं बीटीडी)

एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
CIN : L65993DL1992PLC048753
पंजी. कार्यालय : 8, बालाजी एस्टेट, तृतीय तल, गुरू रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली - 110019
फोन : 91 (11) 41029297, **फैक्स** : 91 (11) 26414900
वेबसाइट: http://www.niit-tech.com; **ई-मेल:** investors@niit-tech.com
सूचना
एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 और 47 के निबन्धनों के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की अगली बैठक मंगलवार, 05 मई, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य के साथ, निम्नलिखित कार्य निष्पादित किए जाएंगे :
1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा-विवरण एवं वित्तीय परिणाम (एकल और समेकित दोनों) तथा उसके संबंध में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य मामलों, यदि कोई, पर विचार, अनुमोदन तथा अभिलेखबद्ध करना।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए तृतीय अंतरिम लाभांश, यदि कोई, की घोषणा के संबंध में प्रस्ताव तथा तृतीय अंतरिम लाभांश, यदि अनुमोदित किया गया, के प्रयोजनार्थ रिकार्ड तिथि निर्धारित की जाएगी।
उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.niit-tech.com/investors/disclosures-under-listing-regulations पर तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेन्ज की वेबसाइट https://www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट https://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।
वास्ते **एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड**
हस्ता/-
तिथि : 29 अप्रैल, 2020 **ललित कुमार शर्मा**
स्थान : नोएडा कम्पनी सचिव एवं विधिक सलाहकार

वोडाफोन आइडिया को धन लौटाए आयकर विभाग

देव चटर्जी
मुंबई, 29 अप्रैल

वोडाफोन आइडिया को आंशिक राहत देते हुए आज सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को आदेश दिया कि वह इस दबावग्रस्त दूरसंचार कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 733 करोड़ रुपये लौटाए जो कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए लंबित है। न्यायालय ने विभाग से यह भी कहा कि वह कर निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 के संबंध में यथा शीघ्र रिफंड कार्यवाही पूरी करे।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वोडाफोन आइडिया को समायोजित सकल राजस्व बकाये और जुर्माने का 53,000 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश दिए जाने के बाद कंपनी को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। वोडाफोन आइडिया को आयकर विभाग से 4,579 करोड़ रुपये के अन्य रिफंड के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए वोडाफोन की तत्कालीन भारतीय कंपनी (वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज) ने आयकर रिटर्न (1,532 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा करते हुए) दाखिल किया है। बाद में नवंबर 2015 में वोडाफोन ने 1,355.51 करोड़ रुपये के अन्य रिफंड का दावा करते हुए कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न दाखिल किया था और एक साल बाद कर निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए वोडाफोन ने 1,128.47 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा किया था। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए वोडाफोन द्वारा 743 करोड़ रुपये के रिफंड का दावा करते हुए कर रिटर्न दाखिल किया गया था। कुल मिलाकर वोडाफोन आइडिया ने कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिए कर रिफंड के रूप में करीब 5,500 करोड़ रुपये की मांग की थी। आयकर रिटर्न की कार्यवाही में विभाग की ओर से पूरी तरह निष्क्रियता दिखाने का दावा करते हुए वोडाफोन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसने न्यायालय से अनुरोध किया था वह विभाग को तुरंत रिफंड प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे। कर विभाग का कहना था कि वोडाफोन की भारतीय कंपनी को रिटर्न देने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जैसे स्थानांतरण मूल्य निर्धारण समायोजन, लाइसेंस शुल्क का पूंजीकरण आदि।

निजी क्षेत्र के बैंकों में बढ़ेगा प्रवर्तक हिस्सा

हंसिनी कार्तिक
मुंबई, 29 अप्रैल

- प्रवर्तकों को हिस्सेदारी 26 फीसदी तक बढ़ाने की मिल सकती है अनुमति
- निजी इक्विटी फर्मों के लिए अधिकतम सीमा 15 फीसदी हो सकती है
- निजी बैंकों में पीई फर्मों की हिस्सेदारी बढ़ने के बावजूद नहीं होगा मतदान अधिकार

निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रवर्तकों और निजी इक्विटी (पीई) कंपनियों की भूमिका कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हो सकती है। इस मामले से अवगत सूत्रों ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक अगले छह से नौ महीने के दौरान इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए बाजार में दस्तक दे सकते हैं। कोरोनावायरस वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार सुस्त पड़ने से लेनदारों को परिसंपत्ति गुणवत्ता में अप्रत्याशित नुकसान होने की आशंका है।

एक सूत्र ने कहा, 'प्रवर्तक अपनी हिस्सेदारी को मौजूदा स्तर से 26 फीसदी तक बढ़ा सकते हैं। निजी क्षेत्र के जिन बैंकों में प्रवर्तकों का निवेश नहीं है उनमें किसी एक पीई को 15 फीसदी तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति हो सकती है।' इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, ऐक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक जैसे बैंकों को इससे फायदा होगा। हालांकि इस तरीके से हिस्सेदारी में बढ़ोतरी किए जाने पर बैंकों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों को झटका लग सकता है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रवर्तकों को अधिक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दे सकता है। पीजे नायक समिति ने 2014 में सुझाव दिया था कि किसी भी बैंक में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी को 25 फीसदी तक रखने की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत कहा गया है कि किसी बैंक में 26 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने वाले उपक्रम को आरबीआई की मंजूरी के बिना मतदान का अधिकार नहीं होगा। हालांकि प्रवर्तकों की ताकत को नियंत्रित करने के लिए वोटिंग अधिकार के लिए 15 फीसदी की सीमा बरकरार रह सकती है। पीई निवेशक सहित गैर-प्रवर्तक शेयरधारकों के लिए किसी बैंक में मंजूरी मार्ग से 10 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है।

सूत्र ने कहा, 'चूंकि ये आरबीआई के नियमों के दायरे में हैं, इसलिए इसके लिए किसी विशेष अधिसूचना अथवा नियामकीय परिपत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल केंद्रीय बैंक से मंजूरी की दरकार है।' रकम जुटाने संबंधी येस बैंक की योजना पर निवेशकों की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं रही है। इसके अलावा पूंजी जुटाने में लक्ष्मी विलास बैंक की असफलता और ऐसे तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए नियामक को पारंपरिक शेयरधारिता ढांचे पर विचार करना जरूरी है।

बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि पूंजी जरूरतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। मझोले आकार के एक निजी बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'लॉकडाउन में विस्तार के बाद परिसंपत्ति गुणवत्ता पर हमें काफी दबाव दिख रहा है। ऐसे में बैंक जल्द से जल्द पूंजी जुटाने की पहल कर सकते हैं।' उन्होंने कहा कि मौजूदा बाजार परिदृश्य को देखते हुए पूंजी जुटाना आसान नहीं होगा। महसूस किया जा रहा है कि इस कठिन दौर में बैंकों के लिए दमदार एवं भरोसेमंद प्रवर्तकों का सहारा काफी मददगार साबित होगा।

यदि किसी बैंक का नियंत्रण गैर-प्रवर्तक निवेश के हाथों में है तो किसी एक पीई को बैंक में 15 फीसदी तक हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पूंजी जुटाने की प्रक्रिया कहीं अधिक कुशलता से समय पर पूरा हो सकेगी। साथ ही शेयर बाजार में हालिया गिरावट को देखते हुए बैंकरों का कहना है कि यदि पीई फर्म किसी बैंक में 5 फीसदी हस्सेदारी खरीदती है तो यह उनके लिए काफी अच्छा रहेगा।

बैंकिंग क्षेत्र पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए थे। आरबीआई ने प्रेम वत्स के नेतृत्व वाली कंपनी फेयरफैक्स को 2018 में सीएसबी बैंक (पूर्व में कैथोलिक सीरियन बैंक) में 51 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति दी थी। इसी साल के आरंभ में बैंकिंग नियामक ने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रवर्तकों को 1 अप्रैल से 15 फीसदी पर मतदान अधिकार के साथ 26 फीसदी हिस्सेदारी की अनुमति दी थी। इसी साल मार्च में इंडसइंड बैंक की प्रवर्तक इंडसइंड होल्डिंग्स ने इस बैंक में 15 फीसदी पर मतदान अधिकार के साथ अपनी हिस्सेदारी 26 फीसदी तक बढ़ाने के लिए आरबीआई से अनुरोध किया था।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-8, सेक्टर-7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301, उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादकः कैलाश नौटियाल
आरएनआई न० DELHIN/2008/27804
पाठक संपादक को **lettershindi@bsmail.in** पर संदेश भेज सकते हैं1
टेलीफोन- 011-23720202-10 फैक्स 011-23720201
सब्सक्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया सम्पर्क करें..
सुश्री मानसी सिंह
हेड कस्टमर रिलेशन्स
बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4 एवं आई/3, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013
ई मेल.. **subs_bs@bsmail.in**
या 57007 पर एसएमएस करें **SUB BS**

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए।
मै0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरु की जाएगी।
कोई हवाई अधिभार नहीं

लॉकडाउन में मोंडलीज का कारोबार बुरी तरह प्रभावित

विवेट सुजैन पिंटो
मुंबई, 29 अप्रैल

- लॉकडाउन के पहले चरण में कंपनी की भारत में बिक्री लगभग शून्य पर आ गई थी
- कंपनी ने भारतीय बाजार का जिक्र करते हुए कहा, कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है
- हालात फिर से पुरानी स्थिति में जा सकते हैं लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा

कन्फेक्शनरी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मोंडलीज ने देश भर में लागू लॉकडाउन से अपना कारोबार बुरी तरह प्रभावित होने की बात करते हुए कहा है कि हालात धीरे-धीरे सुधर रहे हैं।

बड़ी चॉकलेट निर्माता कंपनी के वैश्विक चेयरमैन एवं मुख्य कार्याधिकारी डिर्क वान डि पुट ने बुधवार को निवेशकों के साथ चर्चा में कहा कि लॉकडाउन के पहले चरण में कारोबार पूरी तरह ठप हो गया था और बिक्री भी लगभग नगण्य स्तर पर आ गई थी।

डिर्क ने कहा, जब लॉकडाउन पहली बार लागू किया गया तो अपने कई संयंत्रों में श्रमिकों को पहुंचा पाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन था। इसके साथ ही वितरकों तक माल पहुंचाना भी भारी पड़ रहा था। ट्रकों को जुटाना भी नामुमकिन हो रहा था। उन्होंने कहा कि हालांकि अब हालात बेहतर हो रहे हैं लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि चोट बहुत गहरी लगी है। डिर्क ने भारतीय बाजार का जिक्र करते हुए कहा, कारोबार पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। हालात फिर से पुरानी स्थिति में जा सकते हैं लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा।

पिछले एक हफ्ते में यूनिलीवर से लेकर प्रॉक्टर ऐंड गैम्बल, नेस्ले, कोका कोला और पेप्सिको तक के आला अधिकारी कोविड महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के प्रतिकूल कारोबारी प्रभावों का उल्लेख कर चुके हैं। उनका मानना है कि इसका असर अप्रैल-जून तिमाही के अलावा बाकी समय भी देखने को मिलेगा। गुरुवार को यूनिलीवर ने वर्ष 2020 के लिए अपने वृद्धि एवं मार्जिन अनुमानों को वापस ले लिया था। यूनिलीवर के सीईओ एलेन जोप ने कहा था कि भारत के पूरी तरह थम जाने से उसके कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है।

जोप ने कहा था, भारत हमारे लिए काफी मायने रखता है। हालांकि भारत में हमारा उत्पादन एवं बिक्री पटरी पर लौटा है लेकिन अब भी पूरी क्षमता तक नहीं आ पाया है। हम अब भी वहां पूरी तरह से कारोबार नहीं कर पा रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में हालात सामान्य होने के पहले काफी मुश्किल होंगे।

यूनिलीवर की भारतीय इकाई हिंदुस्तान यूनिलीवर जनवरी-मार्च तिमाही के आंकड़े गुरुवार को जारी करने वाली है। विश्लेषकों का अनुमान है कि उसकी बिक्री में 2-4 फीसदी की गिरावट रह सकती है।

वहीं नेस्ले एसए के सीईओ मार्क श्नाइडर अप्रैल-जून तिमाही के बारे में कुछ भी पक्के तौर पर नहीं कह पा रहे हैं। दरअसल मार्च के दूसरे पखवाड़े में लोगों ने देशव्यापी बंदी के अंदेशे से खान-पान के सामान की जमकर खरीदारी की थी। और नेस्ले के मार्च तिमाही के आंकड़े इसकी तसदीक भी कर रहे हैं। श्नाइडर कहते हैं, हम अपने कारोबार पर कोविड संकट के वित्तीय प्रभावों के बारे में अनुमान नहीं लगा पाएंगे।

Drug to treat Covid ready, says Strides Pharma; stock rises 20%

Firm says will apply to Indian pharma authorities to start studies

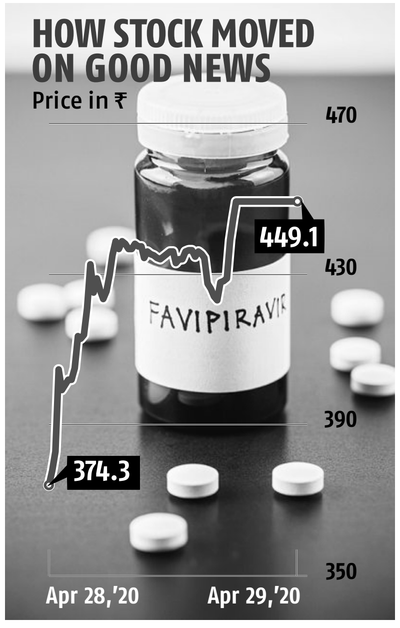

SAMREEN AHMAD
Bengaluru, 29 April

Pharmaceutical manufacturer Strides Pharma Science said on Wednesday it had developed and commercialised an antiviral that has demonstrated positive outcomes in patients who have tested positive for coronavirus disease.

Favipiravir, which is being touted to have proven to reduce duration of Covid and improve lung conditions for patients, is a generic version of Avigan that was initially developed in Japan to treat influenza. It has been called one of the most promising drug against the virus by the government task force.

The product, available in 400 mg and 200 mg strengths, is being exported to Gulf countries. "We are the first Indian company to develop and commercially launch Favipiravir tablets for global markets. This development reinforces our commitment to play a substantial role in society by bringing affordable and quality health care to millions around the globe," said chief executive officer and managing director R Ananthanarayanan.

The company's stock gained 20 per cent to ₹449.1 on BSE. Strides said it will immediately apply to Indian drug authorities to commence necessary studies and make the drug available to Indians expeditiously. The tablets are being manufactured at Strides' flagship facility in Bengaluru, which can produce up to 6 billion units of solid orals annually. The company has entered into a preferred arrangement with an Indian API manufacturer for the supplies of Favipiravir API. "The partner has commercialised the Favipiravir API from its USFDA, KFDA, PMDA and WHO approved manufacturing facility and has capabilities to manufacture the Favipiravir API in-house," the firm said.

CORONAVIRUS PANDEMIC

Several key Indian firms such as Zydus Cadila, Cipla, Glenmark, and Dr Reddy's Laboratories are working on developing antivirals.

Glenmark Pharma has approached the Drug Controller General of India, too, for approval of Favipiravir. It would test the drug on 100-150 patients in a phase-3 trial. This would take around a month as the drug-course is for 14 days. The global market for antiviral drugs has the possibility of surpassing $62.67 billion by 2022.

'We'll have to make sure vaccine's efficacy is high'

Serum Institute Chief Executive **ADAR POONAWALLA** has said his biotechnology firm, in partnership with a consortium led by Oxford University, will roll out a Covid-19 vaccine before the end of the year. Poonawalla tells **Pavan Lall** that his firm — the world's largest manufacturer of vaccines by volume — will be setting up a factory so that work can begin as soon as approvals and trials are wrapped up. Edited excerpts:

You are planning to make a Covid-19 vaccine available at ₹1,000. Isn't that high for millions of low-income households?

Serum Institute is going to supply the vaccine to the government. The Centre will distribute it for free in key and priority areas under the Ayushman Bharat scheme. If you look at the price of a Covid-19 test, it is ₹3,000-4,000. The test has to be undertaken two-three times. This vaccine is economical, considering it is likely to immunise a person for years to come.

Q&A

ADAR POONAWALLA
CEO, Serum Institute

What are the challenges you foresee with any vaccine?

The challenge will be making sure its efficacy is high. If a vaccine is only 50-60 per cent efficient, it's a double-edged sword. Some vaccines we make are more than 95 per cent effective. The data from the trials and the vaccinated groups will show the levels of efficacy from the Oxford project. We're hopeful the results will be good.

Bill Gates said getting the vaccine made is one challenge. The other is ramping up volumes. Are you building a new factory if scaling up is needed? Where will the vaccine be made, in the short term?

We have plans to invest around ₹600 crore in a new factory in Pune. That will be ready in the next few years, with a potential capacity of around 500 million to a billion doses. In the near term, the existing facilities we have include a research and development facility, and a plant that makes pneumonia vaccines. That capacity will be between 50 million and 100 million doses.

Vaccines take years to develop. You have said you won't be able to roll out a vaccine before 2021. What has changed since then?

We had started with a partnership with Codagenix, an American manufacturer. The biotechnology company was engaged in animal testing (on chimpanzees), which can't be done here. That takes time before moving to human testing. The partnership with the Oxford team is further ahead with human trials and will in the future (Phase 2/3) move to testing on thousands of people. This is why we expect to be ready to manufacture by September.

THE DEMAND FOR VACCINES FOR MEASLES, PNEUMONIA AND OTHER DISEASES HAS SLOWED BECAUSE FOCUS IS ON CORONAVIRUS. THERE WILL BE A HUGE OUTBREAK OF INFECTIOUS DISEASES, RESULT IN MORE DEATHS THAN THIS PANDEMIC

Is there a vaccine you will be hitting the pause button on as you switch gears to focus on the Covid vaccine?

The demand for vaccines for measles, pneumonia and other diseases has slowed because the entire focus of the health care system is now on coronavirus. I am willing to put it in writing that there will be a huge outbreak of measles and other infectious diseases which particularly affect the very young. That will result in many more deaths than this pandemic.

Relief to Voda Idea as SC orders ₹733-crore income tax refund

DEV CHATTERJEE
Mumbai, 29 April

In partial relief to Vodafone Idea, the Supreme Court on Wednesday ordered the Income-Tax (I-T) department to refund the telecom company ₹733 crore, pending for the assessment year (AY) 2014-15, within four weeks. The court also asked the department to conclude proceedings relating to the firm's demand of refunds in respect of AY 2016-17 and 2017-18 as early as possible.

Vodafone Idea, which is facing a financial crisis after the apex court ordered it to pay adjusted gross revenue (AGR) dues and penalties totalling ₹53,000 crore, will, however, have to wait for other refunds, worth ₹4,579 crore, from the I-T department.

The court order said that for AY 2014-15, Vodafone's then Indian entities filed income-tax returns (ITRs), claiming a refund of ₹1,532 crore. In November 2015, Vodafone filed returns for AY 2015-16, claiming a refund of another ₹1,355.51 crore.

A year later, the company claimed a refund of ₹1,128.47 crore for AY 2016-17.

For AY 2017-18, Vodafone claimed a refund of ₹743 crore. In total, Vodafone Idea sought around ₹5,500 crore in tax refunds for the period between 2014-15 and 2017-18.

Claiming there was complete inaction on part of the tax department in processing the ITRs, Vodafone had moved the Delhi High Court, asking the court to direct the department to immediately process the refunds.

The tax department said tax returns of Vodafone's Indian entities were facing multiple issues like transfer pricing adjustment, capitalisation of licence fees, 3G spectrum fees, and asset restoration cost obligation, including the effect of amalgamation of group entities, which required thorough scrutiny and determination. The high court dismissed Vodafone's petition in December 2018 and the company then moved the Supreme Court.

The SC in its order said as far as AY 2014-15 was concerned, the final assessment order passed under Section 143(3) of the Act indicated Vodafone was entitled to refunds of ₹733 crore, while for AY 2015-16 there was a demand of ₹582 crore.

The court said the tax department would be entitled to invoke the requisite power under Section 245 of the Act to set off the amount of refund payable in respect of AY 2014-15 against the tax remaining payable.

As the tax department has not taken any action to refund the amount, the SC directed I-T to refund ₹733 crore and take action on other assessment years as soon as possible.

Rakesh Nangia, chairman, Nangia Andersen consulting, said the Supreme Court judgment reinforced the principle that one cannot approach court and seek relief against the procedures prescribed in the statute. "Extraordinary remedy of writ has to be sought in an extraordinary situation, where the authorities have either violated the statutory provisions or exceeded their jurisdiction," he said.

Amit Maheshwari, tax partner, AKM Global, a consulting firm, said the Supreme Court had ruled in favour of revenue.

"This will bolster the case of the tax department wherein there is an ongoing assessment and the tax officer is of the opinion that granting the refund (when there is a likely tax demand) would be prejudicial to the interests of the revenue. This is despite the fact that even if the refund is granted, the tax authorities still have several avenues available to them to recover any future tax demands. This will further delay the refunds processing in several cases and may effect cash flows, hitting companies, especially in the current scenario," he said.

With inputs from Indivjal Dhasmana

TAX TANGLE

- Vodafone Idea, formerly Vodafone Mobile Services, is seeking ₹5,500 crore in tax refund for assesment years 2014–15, 2015–16, 2016–17 and 2017–18
- Telecom company had moved Delhi High Court, seeking expeditious refunds in early 2018
- I–T dept said a thorough examination of Vodafone entities was needed to process refunds
- HC dismissed the petition in December 2018
- Telco moved SC in 2019

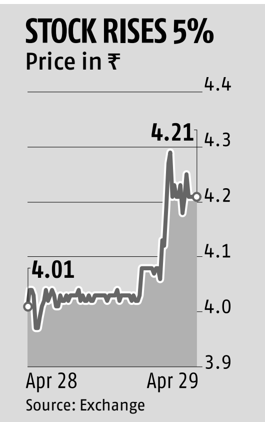

EAST COAST RAILWAY
Tender Notice No. MSM-MCC-OBHS-SBP-1-2020
Name of Work : MECHANIZED CLEANING AND ON BOARD HOUSEKEEPING WORKS OF COACHING DEPOT, SAMBALPUR FOR A PERIOD OF FOUR YEARS.
Approximate Cost of the work (₹) : ₹ 21,65,62,226.64, **EMD :** ₹ 12,32,800.00, **Cost of Tender Document :** ₹ 11,800.00, **Completion Period of the work :** 04 (Four) Years.
Date and time of closing of tender : At 1100 hrs of 18.05.2020
No manual offers sent by Post/Courier/ Fax or in person shall be accepted against such e-Tenders even if these are submitted on firm's letter head and received in time. All such manual offers shall be considered invalid and shall be rejected summarily without any consideration.
Complete information including e-tender documents of the above e-tender is available in website **http://www.ireps.gov.in.**
Sr. Divisional Mechanical Engineer, Sambalpur
PR-11/L/20-21

Astec LifeSciences Limited
Registered Office: "Godrej One", 3rd Floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400079, Maharashtra
Tel. No.: 022-2518 8010, **Fax:** 022-2261 8289, **Website:** www.astecls.com
E-mail: astecinvestors@godrejastec.com
Corporate Identity Number (CIN): L99999MH1994PLC076236
NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT a Meeting of the Board of Directors of Astec LifeSciences Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, 5th May, 2020, *inter alia*, to consider and approve the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2020, after these results are reviewed by the Audit Committee and to consider recommendation of Final Dividend on the Equity Shares of the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020, if any.
This notice is also made available on the website of the Company (www.astecls.com) and on the websites of BSE Limited (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed.
Pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 ("PIT Regulations") and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading ("the Code"), the Trading Window for dealing in the securities of the Company is closed with effect from Wednesday, 1st April, 2020 to Thursday, 7th May, 2020 (both days inclusive), for all the Directors and Designated Persons of the Company and their immediate relatives as defined in the PIT Regulations and the Code, for the purpose of approval of the Standalone and Consolidated Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2020.
For Astec LifeSciences Limited
Sd/-
Tejashree Pradhan
Company Secretary & Compliance Officer
Place : Mumbai
Date : 30th April, 2020

INDIAN PORT RAIL & ROPEWAY CORPORATION LIMITED
(A JV Company under Ministry of Shipping, Government of India)
(Formerly Indian Port Rail Corporation Ltd.)
SAGARMALA
RFQ No. IPRCL/ADI/PROJECTS/NMHC/EPC/2020
Dated: 30.04.2020
Construction of National Maritime Heritage Complex at Lothal, Gujarat through Engineering, Procurement & Construction (EPC) Mode.
For more details visit website www.etenders.gov.in/eprocure/app

Business Standard
MUMBAI EDITION
Printed and Published by Sangita Kheora on behalf of Business Standard Private Limited and Printed at M/s. Dangat Media Private Limited, 22 Digha M.I.D.C., TTC Industrial Area, Vishnu Nagar, Digha, Navi Mumbai, 400708 and M/s. Nai Dunia 23/4, 23/5, Sector-D, Industrial Area, J.K. Road, Near Minal Residency, Bhopal (M.P.)-462023. & Published at H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai- 400013
Editor : Shyamal Majumdar
RNI NO: 66308/1996
Readers should write their feedback at **feedback@bsmail.in**
Fax : +91-11-23720201
For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited.
H/4 & I/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centurion, P.B.Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in
"or **sms**, SUB BS to 57007"
Overseas subscription: (Mumbai Edition Only)
One year subscription rate by air mail INR 51765 : USD 725

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement.
Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned.
Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or redissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.
No Air Surcharge

Gujarat Informatics Limited
Enabling e-Governance
Block no. 2, 2nd Floor, Karmayogi Bhavan, Sector 10 A, Gandhinagar-382010 (Gujarat) Ph. : 079-23256022, Fax: 079-23238925
NOTICE FOR INVITING BIDS
GIL invites bids through E-tendering for Selection of Agency for Supply, Installation, Commissioning & Warranty Support of various Equipment's for the Implementation of Thermal Screening System for various offices and public places of Gujarat State (Tender No. HWT290420615).
Interested parties may visit **http://www.gil.gujarat.gov.in** or **https://www.gil.nprocure.com** for eligibility criteria & more details about the bids.
- Managing Director

RITES LIMITED (A Govt. of India Enterprise)
THE INFRASTRUCTURE PEOPLE
BHUBANESWAR-751024
Notice Inviting e-Tenders
The Group General Manager (Civil), RITES Ltd, Bhubaneswar, invites on behalf of **M/s. NSPCL, Rourkela,** percentage rate bids on two packet system for the following work(s):
NIT No. OT/01/2020/RITES/BBSR/NSPC/S&T, Dated: 30.04.2020
Name of Work: **"Supply, Installation, Testing & Commissioning of Electronic Interlocking System along with all the outdoor gears, cables etc. for Provision of new Electronic Interlocking arrangement at NSPCL Yard, Rourkela along with Provision of Inter-Slotting arrangement with OBBP and Marshaling yard of SAIL/RSP."** Estimated cost: ₹ **13,84,45,466.00** Earnest Money: ₹ **13,84,455.00,** Period of Completion: **09 (Nine) months,** Last time and date of submission of bid : **15:00 Hrs (IST) of 22.05.2020.** The bid forms and other details can be obtained from the website: **https://etenders.gov.in/eprocure/app**.
Addendum/Corrigendum, if any, shall be hoisted online only.

TAMILNADU INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD (TIDCO)
CIN-U65993TN1965SGC005327
NOTICE NO. TIDCO/CONSULTANT/2020-21
TIDCO invites quotations from professional consulting agencies for conducting due diligence of a potential investment opportunity. Interested Firms requested to obtain more information including Terms of Reference from the website **www.tidco.com.** Last date and time for submission of quotations is on or before 15:00 Hrs on 13.05.2020.
EXECUTIVE DIRECTOR
Tamilnadu Industrial Development Corporation Ltd
19-A, Rukmani Lakshmipathi Salai, Egmore, Chennai - 600 008
Ph: 044 - 28551500; Fax: 044 - 28553729
E-mail: ed@tidco.com; Website: www.tidco.com
DIPR/493/DISPLAY/2020

यूको बैंक **UCO BANK**
Honours Your Trust
(A Govt. of India Undertaking)
Head Office – II, Department of Information Technology
3 & 4, DD Block, Sector – 1, Salt Lake, Kolkata–700064
NOTICE INVITING TENDER
UCO Bank invites Request for Proposals (RFPs) for the following:
1. Request for Proposal (RFP) for Selection of SMS Aggregator for Implementation of SMS and Co-Related Services.
2. RFP for Selection of IT consultant on Retainer Basis.
3. RFP for Selection of Vendor for Implementation of National Electronic Toll Collection (NETC) as an issuer under OPEX Model for Issuance of FASTag.
For any details, please refer to **https://www.ucobank.com**.
Date:30.04.2020 **Deputy General Manager (DIT, BPR & BTD)**

यूको बैंक **UCO BANK**
Honours Your Trust
(A Govt. of India Undertaking)
Risk Management Department
Head Office, 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700 001
NOTICE
Request for Proposal (RFP) for Engagement of a Credit Rating Agency for **Recalibration / Design / Vetting of the Internal Credit Rating Models and hoisting** on Bank's portal. Please visit Bank's website **https://www.ucobank.com** for details.

ONGC Petro additions Limited
Reg. Office: 4th Floor, 35, Nutan Bharat Co-operative Housing Society Limited, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390007, Gujarat. Ph.: 0265 6192600 CIN No.: U23209GJ2006PLC060282
ओपीएएल OPaL
TENDER NOTICE
OPaL invites the sealed tender under Open Tender Two Bid System for: **Tender Number:** 2004C00290; **Tender Description:** Hiring of Light Commercial Vehicles within Gujarat; **Tender Sale Period:** 30.04.2020, 09:00 Hrs to 21.05.2020, 14:00 Hrs; **Closing date and time for Bid Submission:** 21.05.2020, 14:00 Hrs.
The tender document can be downloaded from OPaL website (**www.opalindia.in**). For other details of this tender including corrigendum if any, please logon to OPaL website "**www.opalindia.in**". In case of exigencies OPaL at its option may decide to extend tender sale/bid closing/ opening date/ time in future, which will be posted on the above referred website for information. Bidders should regularly visit OPaL website for the latest information in this regard.

TELANGANA STATE POWER GENERATION CORPORATION LIMITED
VIDYUT SOUDHA: HYDERABAD - 500 082.
T.No.e-01/CE/Civil/Hydel & GS/TSGENCO/2020-21
LJHEP – Construction of RR Masonry Basement and providing chain link mesh fencing along L/s river bank of Krishna River at LJHEP, Atmakur, Value of the works: `.55,75,043/-. Scheduled Open & Closing Date: **24.04.2020 at 17:00 Hrs & 18.05.2020 at 16:00 Hrs.**
T.No.e-08/CE/O&M/KTPS-V&VI Stages/DEP1/BM-V/P12/2020-21
KTPS-V&VI Stages – Procurement of "2 ½" 3000 Class WC9 EMRV Isolation Gate Valve Assembly with ¾ Equalisation valve for KTPS-V Stage at Paloncha, Bhadradri Kothagudem Dist – Value of the works: `.18,76,170/-. Scheduled Open & Closing Date: **28.04.2020 at 17:00 Hrs & 20.05.2020 at 15:30 Hrs.**
Details: " www.tsgenco.co.in & https://tender.telangana.gov.in"

NIIT Technologies Limited
NIIT technologies
CIN : L65993DL1992PLC048753
Regd. Office: 8, Balaji Estate, Third Floor, Guru Ravi Das Marg, Kalkaji, New Delhi – 110 019
Ph: 91 (11) 41029297, **Fax:** 91 (11) 26414900
Website: http://www.niit-tech.com; **Email:** investors@niit-tech.com
NOTICE
Notice is hereby given pursuant in terms of Regulation 29 and 47 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the next meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, May 05, 2020, inter-alia, to transact, the following businesses:
1. To consider, approve and take on record the Audited annual accounts and Financial Results for the quarter/year ended March 31, 2020 (both Standalone and Consolidated) alongwith Auditors Report thereon and other matters, if any.
2. The proposal relating to declaration of third Interim Dividend, if any, for the Financial Year 2019-20 and will determine the Record Date for the purpose of the third Interim Dividend, if approved.
The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.niit-tech.com/investors/disclosures-under-listing-regulations and also on the website of National Stock Exchange at https://www.nseindia.com and BSE Limited at https://www.bseindia.com
For **NIIT Technologies Limited**
Sd/-
Lalit Kumar Sharma
Company Secretary & Legal Counsel
Dated : April 29, 2020
Place : Noida

asianpaints
Asian Paints Limited
CIN : L24220MH1945PLC004598
Regd. Office: 6A Shantinagar, Santacruz (East), Mumbai-400 055
Tel. No.: (022) 6218 1000
website: www.asianpaints.com
email: investor.relations@asianpaints.com
NOTICE
TRANSFER OF THE EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND
This Notice is hereby given to the shareholders of the Company pursuant to Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("IEPF Rules"), as amended from time to time.
In terms ofthe provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the IEPF Rules, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more are liable to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF").
In view of the outbreak of COVID-19 pandemic in India, the Company is unable to send individual notices to those shareholders who have not claimed their dividend for seven (7) consecutive years or more in term of IEPF rules. The Company shall dispatch notices to aforesaid shareholders at their registered address once the normalcy resumes, inter alia, providing them the details of their unclaimed dividend and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by **Wednesday, 15th July, 2020**, to avoid transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority.
In terms of Rule 6 of IEPF Rules, a statement containing details of the name(s) of the shareholder(s) and their Folio number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on our website www.asianpaints.com for information and necessary action by the shareholder(s).
In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the shareholders by **Wednesday, 15th July, 2020**, the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that-
i. *For Shares held in physical form:* New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.
ii. *For Shares held in electronic form:* The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.
It may be noted that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend and shares transferred to IEPFpursuant to IEPF Rules. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online applicationfor which the details are available at www.iepf.gov.in.
In case of any queries/clarifications, the concerned shareholders may contact the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s. TSR Darashaw Consultants Private Limited quoting the Folio number/ DP ID-Client ID at:
TSR DARASHAW CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
(Unit: Asian Paints Limited)
6-10, Haji MoosaPatrawala Industrial Estate,
20, Dr. E. Moses Road, Near Famous Studio,
Mahalaxmi, Mumbai 400 011.
Tel: +91 22 6656 8484
Toll Free number – 18002100124
Email: csg-unit@tsrdarashaw.com
For **ASIAN PAINTS LIMITED**
Sd/-
R J JEYAMURUGAN
CFO & COMPANY SECRETARY
Place : Mumbai
Date : 29/04/2020